THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI JASWANT SINGH): Madam, on behalf of the Government, I would like to assure all the hon. Members who have raised this issue that this is a subject that the Government of India has taken up already. We have considered it as a very important aspect of Indo-Sri Lankan relations. There is also the very important aspect of fishing rights in those territorial waters. Now, we will, definitely -- I would like to assure the hon. Members -- take up this with the appropriate authority and in an appropriate fashion with the Government of Sri Lanka and the arrangements will be made for the earliest possible release of the fishermen that are now under custody, as also the release of boats, etc. I would like to assure this to the House. Thank you.

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : महोदया, इससे पहले मैं डा. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष मे अपने विचार प्रकट करुं, मैं आपकी अनुमति से क्वालालम्पुर में हुए गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन में हुए भाषण को सभापटल पर रखना चाहूंगा।

महोदया, गुट-निरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोगिता है, इस पर चर्चा होती रही है। हमारा स्पष्ट मत है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी भी प्रासंगिक है, उपयोगी है और विश्व की व्यवस्था को शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण बनाने मे महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है । 'नेम' के सदस्य राष्ट्रों की भी यही राय है । क्वालालम्पुर मे एक सौ सोलह राष्ट्रों का सम्मेलन, उनमें गंभीर विचार-विनिमय, एक मत से निर्णयो का लिया जाना, इस बात का संकेत है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में समर्थ है । निस्संदेह विश्व मे एक नई परिस्थिति पैदा हुई है । शीत युद्ध समाप्त हो गया है और विश्व को बहुध्रुवीय बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता होगी । इसीलिए यह तय हुआ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हम और शक्तिशाली करें । उसको परिभाषित करे और उसके द्वारा युद्ध और शांति के साथ-साथ ऐसे सवाल उठाएं जिनका गुटनिरपेक्ष राष्ट्रो के साथ संबंध है । इस संबंध में वहां क्वालालम्पुर में एक विशेष पहल की गई, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा । हम साउथ-साउथ कोआपरेशन की बात करते हैं । हम नॉर्थ-साउथ कन्फ्रन्टेशन की बात भी करते हैं लेकिन इससे समस्या का समाधान नही होगा । साउथ-साउथ का तो सहयोग होना चाहिए लेकिन जब हम नॉर्थ से संबंध रखना चाहते हैं तो संबंध मुठभेड़ के संबंधो मे बदल जाते हैं । ऐसा लगता है कि उत्तर एक ओर खड़ा है, दक्षिण एक ओर खड़ा है । क्वालालम्पुर में यह विचार हुआ कि हमे ऐन्गेजमेन्ट की भाषा बोलनी चाहिए । जैसे साउथ-साउथ के देश आपस मे एक-दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं, और करना चाहिए । उसी प्रकार से साउथ और नॉर्थ के बीच मे भी आदान-प्रदान होना चाहिए । सहयोग के रास्ते खुलने चाहिए । जहां मतभेद हैं वे मतभेद स्पष्ट रूप से सामने आएंगे । उनके

निराकरण का प्रयास किया जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन उसमें अपनी भूमिका अदा कर सकता है । विकासशील देशों की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं में काफी समानता है। हम एक-दूसरे को ...(**व्यवधान**)... करते हैं और एक-दूसरे को बहुत-कुछ सहयोग भी दे सकते हैं । प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा के भाषण से मैं काफी प्रभावित रहा । ये थाइलैण्ड के प्रधानमंत्री हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने के लिए और रोजगार को बढ़ाने के लिए थाइलैण्ड ने वन विलेज, वन प्रोडक्ट जैसे कुछ कारगर प्रयोग उपयोग किए हैं । कुछ अच्छे प्रयोग बंगलादेश में भी हुए हैं । भारत उन प्रयोगों का लाभ उठा सकता है लेकिन यह जरूरी है कि एक-दूसरे के प्रयोगों के बारे में आपस में सूचना दी जाए । किस देश में कहां क्या हो रहा है । सबके सामने गरीबी की समस्या है । उससे किस तरह से लड़ा जाए । अभी सूचना के आदान-प्रदान का भी कोई प्रबंध नहीं है । यह बहुत आवश्यक है । इस पर बल दिया गया है । जहां तक भारत का संबंध है तो हमने क्वालालम्पुर में यह सुझाव रखा है कि ग्लोबल पॉवर्टी एलिविएशन फंड स्थापित किया जाए । उसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में होने वाली धनराशि के विनिमय पर एक छोटा सा कर लगाकर ऐसा फंड बनाया जा सकता है जो गरीब देशों के काम आ सकता है । वे इसका लाभ उठा सकते हैं । मैं चाहूंगा कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की उपलब्धियों के बारे में या उसकी कमियों के बारे में सदन में चर्चा हो । विद्वान सदस्य अपनी-अपनी राय से हमें लाभान्वित करें । एक और प्रश्न चर्चा के दौरान उठाया गया जो कि जम्मू-कश्मीर का प्रश्न था । विरोधी दल के नेता डा. सिंह ने इस मामले को उठाया । उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि वहां चुनाव हुए और उससे सभी लोग प्रसन्न हैं । यह बात अलग है कि जब दो साल पहले चुनाव की बात हुई थी तो बड़ी निराशाजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी, जब हमने कहा कि हम चुनाव कराना चाहते हैं और विश्वास दिलाया कि हम निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं तो लोगों के मन में संदेह थे । वर्षों की पृष्ठभूमि के कारण ये संदेह हों यह स्वाभाविक भी है । लेकिन सरकार का निश्चय पक्का था । समय पर चुनाव हुए और निष्पक्ष चुनाव हुए । सारे संसार ने उन चुनावों की तारीफ की है । इन चुनावों के साथ जम्मू-कश्मीर में और जम्मू-कश्मीर के इतिहास में एक नए अध्याय का श्रीगणेश हो गया है । कुछ सदस्यों ने कहा और डा. मनमोहन सिंह का भी उसमें उल्लेख है कि अब जम्मू-कश्मीर सरकार को केन्द्र की ओर से सहायता दी जानी चाहिए या जिसका एलान किया गया है वह सहायता मिलनी चाहिए । मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जम्मू-कश्मीर के बारे में अब वे गलतियां नहीं होंगी जो गलतियां पहले हो चुकी हैं । जब मैं कहता हूं कि नए अध्याय का श्रीगणेश हुआ है तो नया अध्याय हर क्षेत्र में खुलेगा, हर प्रश्न को लेकर उद्घाटित होगा । लोगों ने बड़ी आशा और विश्वास के साथ मताधिकार का उपयोग किया है । गोली का सामना किया है, पड़ोसी को करारा जवाब दिया है । उम्मीदवार अपनी जान पर खेल गए । मतदाता अपनी जान खतरे में डाल कर वोट डालने के लिए आए । विश्व की परिस्थिति पर भी इसका असर हुआ है । हमने जो भी सहायता का एलान किया है उस पर हम पूरा आचरण करेंगे । वहां बात-चीत करने के लिए श्री एन.एन. वोहरा की नियुक्ति की गई है । वे पुराने, मंझे हुए और अनुभवी अधिकारी हैं । वे वहां सब से बात-चीत करेंगे और समस्याओं के समाधान में सहायक होंगे । डा. मनमोहन सिंह जी ने 6 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का उल्लेख किया है और मुझे याद दिलाया है कि 6 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का आपने वहां एलान किया था । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 6 हजार करोड़ रुपये का वह पैकेज अपनी जगह पर कायम है । वह पूरा खर्चा होगा, लेकिन उसमें से अधिकांश रेलवे लाइन पर खर्च होगा, यह आप ध्यान रखिए, क्योंकि हम श्रीनगर तक रेलवे लाइन चाहते हैं । स्व. राजीव गांधी

के जमाने में भी रेलवे लाइन को आगे ले जाने का फैसला हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से वह काम रुक गया । यह काम बड़ा महत्वपूर्ण है । एक बात मैंने सरकार में देखी है, चार-पांच साल हो रहे हैं, अगर काम करना है तो फिर पैसे की कमी आड़े नहीं आती, लेकिन अगर नहीं करना है तो फिर पैसा नहीं है । यह बात बिल्कुल साफ है । किसने सोचा था कि सड़कों के लिए, राजमार्गों के लिए हम इतनी भारी धनराशि इकट्ठी कर लेंगे । यह किसने सोचा था ? ...**(व्यवधान)**... लेकिन सड़कें बन रही हैं । ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : अभी बीच में मत बोलिए । I would be very thankful to the Members of the House if they let the hon. Prime Minister speak. ...*(Interruptions)*... They can put their questions, later on. ...*(Interruptions)*...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : रेलवे का भी विस्तार हो रहा है, केवल सड़कों का ही नहीं । जहां तक जम्मू-कश्मीर का सवाल है, वहां के मुख्य मंत्री श्री मुफ्ती जी से हम लोगों का निकट संपर्क है । पार्टी भिन्न होते हुए भी उन को विश्वास रखना चाहिए कि जहां तक जम्मू-काश्मीर का मामला है, सारा सदन और सारा देश एक है । अगर हमारे जवान जम्मू-काश्मीर के लिए जान दे सकते हैं तो क्या हम छोटे-मोटे मतभेद भुलाकर इस सदन में और सदन के बाहर कंधे-से-कंधा लगाकर काम नहीं कर सकते ?

राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण, मैं नहीं जानता उस को "maiden" कहा जाय या नहीं कहा जाय, लेकिन जो भी व्यक्ति पहली बार राष्ट्रपति बनेगा और पहला भाषण देगा, वह "maiden" भाषण तो देगा ही । कोई बासी भाषण नहीं दे सकता, ताजा भाषण देगा ।

उपसभापति : उस में इंटरप्शंस भी नहीं होते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस में इस बात पर बल दिया गया है कि हमें विकास की दर को बढ़ाना है । "विजन 2020" की बात की गयी है । अब कोई कह सकता है कि आप तो सपने देखते हैं । यह 8 परसेंट रेट ऑफ ग्रोथ कैसे होगी ? अभी तो यह थोड़ी सी और घट गयी है, आगे भी आसार अच्छे नहीं दिखाई देते हैं । मैं मानता हूं, इस बार खेती के मोर्चे पर विफलता के कारण आर्थिक विकास की दर धीमी पड़ गयी है । दो साल हम सूखे का सामना करते रहे हैं और उस के बाद भी मैं जानता हूं कि और समस्याएं हैं, उन का निराकरण भी करना पड़ेगा । लेकिन देश में एक संकल्प होना चाहिए । मुख्य मंत्रियों की बैठक में भी हम ने इस पर चर्चा की, अधिकारियों से भी विचार-विमर्श किया । उस में एक स्वर निकलता था कि साहब, काम बहुत कठिन है, उन्हें तैयार किया गया कि काम कठिन है, मगर काम असंभव नहीं है । सारा देश अगर जुट जाय, राजनीतिक मतभेद, चुनाव की चिंता थोड़ी देर के लिए अगर हम ताक पर रख दें और सोचें कि राष्ट्र के विकास की दर बढ़ानी है तो 8 परसेंट विकास दर प्राप्त करना असंभव नहीं होना चाहिए । ...**(व्यवधान)**... उपसभापति महोदया, "विजन 2020" में चार तरह की कनेक्टिविटी की बात कही गयी है । अब इस बारे में सवाल होता है कि कहां से और कैसे कनेक्टिविटी होगी ? पैसा कहां से आएगा? राज्यों के पास तो धन नहीं है, राज्यों की हालत अच्छी नहीं है, यह हम सब जानते हैं । यह क्यों अच्छी नहीं है, यह एक दिन बहस का विषय हो

सकता है, लेकिन फिर भी धन तो जुटाना पड़ेगा और मैं कहना चाहता हूं कि जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, चार कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो उसे भविष्य के ऊपर नहीं डालते हैं । हम यह काम इस समय कर के दिखा रहे हैं । राष्ट्रपति जी ने संकल्पना में कनेक्टिविटी की चार बाते कही हैं - फिजिकल कनेक्टिविटी यानी अच्छे रास्ते होने चाहिए, बिजली होनी चाहिए, आवागमन होना चाहिए । यह हम अभी कर रहे हैं और तेजी से करने की जरूरत है । इस के लिए धन जुटाना होगा । टेलिकॉम तथा इंटरनेट सेवाएं - यह इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी है । इसे गांव-गांव मे पहुंचा रहे हैं, लोग उस का लाभ उठा रहे हैं । किसी ने सोचा भी नही था कि मंडी में बैठी हुई हमारी तरकारी बेचने वाली बहन सेल्युलर का बटन दबाकर ...**(व्यवधान)**... आज का ताजा भाव पूछेगी ...**(व्यवधान)**... आज का ताजा भाव पूछेगी और सब से अच्छे भाव मे जहां मंडी मे माल बिक रहा है, वहां माल भेजेगी । ...**(व्यवधान)**...

श्री लालू प्रसाद (बिहार) : मंडी के साथ-साथ अयोध्या से बात कर लेगे, ये आप के साधु लोग। ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down ...*(Interruptions)*... Please, take your seats...*(Interruptions)*...

श्री लालू प्रसाद : मंडी के साथ-साथ अयोध्या से बात कर लेगे, ये आप के साधु लोग। ...**(व्यवधान)**... मैडम, इनकी उपलब्धि है साधु जुटे तो एक हाथ मे गांजे की चिलम और दूसरे मे मोबाइल। यह तो इनकी उपलब्धि है। ...**(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदया, अगर माल खेत से निकलकर मंडी मे पहुंचे तो इसके लिए भी सड़क चाहिए, साधन चाहिए, परिवहन चाहिए, बिक्री-खरीद का अच्छा इंतजाम चाहिए।

इसके आगे एक और कनेक्टिविटी है नॉलेज कनेक्टिविटी। यह नॉलेज का युग है। इस चर्चा के दौरान राज्यसभा मे एक बहुत अच्छे मुद्दे पर बहस हुई, वह है सर्वशिक्षा अभियान। सरकार बंध गई है, संविधान ने निर्देशित किया है, हर बच्चे को शिक्षा देनी होगी। भार है, सरकार को उठाना पड़ेगा। मगर, इसके साथ ही डा. अलेक्जेन्डर जी ने कहा, वे शायद इस समय सदन मे नही हैं।

उपसभापति : हैं, बैठे है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होने उच्च शिक्षा की बात कही और कहा कि उच्च शिक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, उच्च शिक्षा का स्तर गिरना नहीं चाहिए, उच्च शिक्षा को और बढ़ाने फैलाने की, उसमे अनुसंधान करने की आवश्यकता है। दोनो बातों मे सत्य है, दोनो पहलू आवश्यक हैं। अब इनमे संतुलन कैसे बैठाया जाए? यह राज्य का कर्त्तव्य है, यह बुद्धिजनो का दायित्व है। हम शिक्षा सबको देना चाहते हैं, यह सही है। लेकिन, हम उच्च शिक्षा के जो अधिष्ठान हैं, प्रतिष्ठान हैं उनकी योग्यता मे, उनकी क्षमता मे भी किसी तरह की कमी नही आने देना चाहते। इसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करने की जरूरत है।

महोदया, आज भारत की चारो क्षेत्रो मे तस्वीर बदल रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 7000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना शुरू हुई है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण प्रदेश सरकारो की जिम्मेदारी है, परन्तु पहली बार केन्द्र सौ प्रतिशत धनराशि मुहैया कराके राष्ट्रीय विकास की इस प्राथमिकता को पूरा कर रहा है। लगभग 7000 करोड़ रुपए राज्यो को दिए गए हैं। मुझे बताया गया है कि विभिन्न प्रदेशो के लिए 20,000 गांवों में यह काम शुरू हुआ है, लेकिन यह बात भी सच है कि अभी तक 1,60,000 गांव ऐसे हैं, जो अच्छी सड़को से जुड़े हुए नही हैं। हमने अभी तक सड़कों की चिंता नही की, उसकी उपेक्षा हुई और उससे कितना घाटा हुआ, मैं विस्तार से उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन, अब हम ध्यान दे रहे हैं तो साधनो की समस्या को हल करना पड़ेगा।

इसी तरह, महोदया, इलेक्ट्रोनिक कनेक्टिविटी मे भी आज ग्रामीण भारत को तेजी से जोड़ा जा रहा है। गांव मे अब टेलीफोन, मोबाइल फोन तथा इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। वर्ष 1999 से अब तक यानि तीन सालो में ग्रामीण क्षेत्रो में कनेक्टिविटी तीन गुना बढ़ी है। अभाव की अर्थव्यवस्था मे आज भारत विपुलता की अर्थव्यवस्था मे कदम रख रहा है। इसके लिए पूरे भारत की तस्वीर को एक तस्वीर का रूप देने का हमारा प्रयास है। कृषि को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश मे ले जाने मे कोई कठिनाई नही होना चाहिए। दिल्ली निश्चय करता है, मगर उस पर अमल नही होता है। राज्य स्वीकार कर जाते हैं कि बिना रोकटोक के फसल जाने देना चाहिए, उत्पादन को जाने देना चाहिए, मगर व्यवहार में कठिनाइयां खड़ी हो जाती हैं। इससे प्रगति रुकती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कनेक्टिविटी के इन चार लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पांच लाख करोड़ रुपए के निवेश का हमारा लक्ष्य है। बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैंने जीडीपी की स्थिति का उल्लेख किया। सूखे के कारण उसमे कुछ मंदी आई है। वैसे तो सारा विश्व इस समय वित्तीय और आर्थिक कठिनाइयो से ग्रस्त है। कृषि में विकास बहुत घटा है। इससे इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि सूखे की गंभीरता कितनी है। लेकिन इस कठिन परिस्थिति मे भी उत्साहजनक पहलू हैं। हमारा निर्यात बढ़ा है।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : लेकिन खाद्यान्न भी नही देते।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे पास है ।

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल) : विदेशी मुद्रा खाएंगे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री प्रणब मुखर्जी ने विकास की दर बढ़ाने के लिए बचत प्रतिशत मे वृद्धि करना जरूरी है, यह कहा। मैं उनसे सहमत हूं। किन्तु इस संबंध मे भी दो विचार प्रकट होते हैं। एक तो यह दावा किया जाता है कि The Gross Domestic Savings as a proportion of GDP at current market prices increased from 23.4 per cent in 2001 to 24.0 per cent in 2001-2002. बचत कम नहीं हुई है, बढ़ी है।

श्री नीलोत्पल बसु : बहुत वृद्धि हुई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब इसको चुनौती दी जा सकती है।

श्री नीलोत्पल बसु : बोल रहे हैं न कि बहुत वृद्धि हुई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक और धर्म संकट है, मैं यह खड़ा करना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

DR. ALLADI P. RAJKUMAR (Andhra Pradesh): Madam, this is very bad. When the hon. Prime Minister is replying, let him reply ...*(Interruptions)*... He should not be interrupted by the hon. Member. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: You don't have to teach us. Questions have been raised, but he has not answered ...*(Interruptions)*... I am not required to learn lessons from your leader, Chandrababu Naidu ...*(Interruptions)*...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदया, ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Both of you sit down please. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Dr. Rajkumar, don't teach us lessons. ...*(Interruptions)*....

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: You have to learn lessons sometimes. ...*(Interruptions)*...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदया, ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please take your seats. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सरोज दुबे : ये हमारी ज़बान नही बंद कर सकते, हमें बोलने से नहीं रोक सकते। ...**(व्यवधान)**...

SHRI RUMANDLA RAAMACHANDRAYYA (Andhra Pradesh): Why did you take the name of our leader? ...*(Interruptions)*...

उपसभापति : मिस्टर बसु, प्लीज़ सिट डाउन । ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए । आप बैठ जाइए । ...**(व्यवधान)**... मैं बैठा रही हूं आपको । प्लीज़ सिट डाउन । ...**(व्यवधान)**... प्लीज़। देखिए, हमारी परम्परा है कि अगर लीडर आफ दि अपोजीशन भी बोलते हैं तो सब खामोशी से सुनते हैं । अब अगर प्रधान मंत्री बोल रहे हैं तो उनके भाषण को आप सुनिए, उन्हें जवाब देने दीजिए । बीच-बीच में ...**(व्यवधान)**... एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए । ...**(व्यवधान)**... Nilotpalji, When I am speaking, you are interrupting me also. ...*(Interruptions)*... Let us listen ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Who are interrupting you, Madam? ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You are not interrupting me. Don't interrupt anybody. Let the speech be over. We had a discussion on the Motion of Thanks on the President's Address, and it is the duty of the hon. Prime Minister to reply. He is doing it. We have to listen to it with peace. ...*(Interruptions)*...

श्री सुरेश पचौरी : मैडम, हम लोगों को बाद मे पूछने का मौका मिलेगा ?

SHRI NILOTPAL BASU: He is avoiding certain issues. ...*(Interruptions)*...

उपसभापति : अभी भाषण खत्म नही हुआ है। Mr. Suresh Pachouri, that statement is not yet over. I am not giving any commitment. You sit down please. ...*(Interruptions)*... Let me first hear the speech ...*(Interruptions)*... I will not allow any more interruptions. ...*(Interruptions)*...

श्री लालू प्रसाद : मैडम, ये कुछ बात बोल रहे थे, इससे तो प्रधान मंत्री को लाभ हो गया। बैठ गए, थोड़ा आराम भी हो गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदया, लालू जी कभी-कभी बड़ी मार्मिक बात कहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती जमना देवी बारुपाल (राजस्थान) : महोदया,.....

उपसभापति : अभी आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... बैठ जाइए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपसभापति महोदया, मैं यह बात कह रहा था कि बचत ज्यादा होनी चाहिए। थोड़ी वृद्धि हुई है मगर उतनी पर्याप्त नही है। लेकिन कठिनाई यह है कि

देश में एक और विचार-धारा चल रही है जो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खर्च करो। लेकिन खर्च करने के लिए पहले कमाना जरूरी है और इमानदारी के तरीकों से कमाना जरूरी है। अब खर्च बढ़ाने के लिए यह हमारे वित्त मंत्री जी का ...**(व्यवधान)**...

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश): आपकी बात पर राजनाथ सिंह जी हंस रहे हैं, आप देख लीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदया, सुख सुविधाओं वाली वस्तुओं पर कम ब्याज लिया जाता है, आवश्यक वस्तुओं पर ज्यादा ब्याज की दर ली जाती है। यह चर्चा का विषय रहा है और इसीलिए वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट में कृषि, कृषि उद्योग, लघु उद्योग तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ब्याज दर में कमी की है। ...**(व्यवधान)**... महोदया, डा0 सिंघवी ने जिन्होंने धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया था अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र तथा विकास के विकेन्द्रीयकरण को साथ-साथ लेकर आगे चलना चाहिए। पंचायतों को शक्ति प्रदान करने की दिशा में अब तक जो प्रगति हुई है उस पर भी डा0 सिंघवी ने प्रकाश डाला है। 13वें और 14वें संवैधानिक संशोधन के दस साल पूरे हो गए हैं। इन संशोधनों का श्रेय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को दिया जाता है। 34 लाख प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। इस विराट देश के लिए और कठिनाईयों में फंसे हुए देश के लिए एक उल्लेखनीय सफलता है। इनमें से एक तिहाई महिलाएं हैं। लेकिन सशक्तिकरण का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि पंचायतों के पास धन नहीं है। वित्तीय कठिनाई है। इस कठिनाई के कारण वे अपनी इच्छा की विकास की योजनाओं को हाथ में नहीं ले सकतीं, पूरा नहीं कर सकतीं। इस पर चर्चा हुई है तथा एक सम्मेलन भी हुआ था। श्री वेंकैया नायडु उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने सम्मेलन का आयोजन किया था। सर्वानुमति से यह तय हुआ कि आर्थिक और प्रशासनिक सशक्तिकरण किया जाए। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। सरकार उसके लिए तैयार है, हम सब दलों का उसमें समर्थन चाहते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं। पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने की बात है। लेकिन चुनकर भेज देना काफी नहीं है, कठिनाईयां होंगी और जो ऊपर चुनकर गया है उससे मुठभेड़ भी होगी। लेकिन रास्ता निकालना पड़ेगा। हम पंचायतों का निर्माण करें और उन्हें बिल्कुल साधन-विहीन छोड़ दें तो भी निराशा बढ़ेगी और जो सपना राजीव गांधी ने देखा था और उनके साथ हमने भी देखा था वह पूरा नहीं होगा। अगर सुझाव स्वीकार हो तो हम इस सत्र में एक संयुक्त अधिवेशन इस सवाल पर बुला सकते हैं और संविधान में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। डा. मनमोहन सिंह ने एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या पर ध्यान खींचा है। कई राज्यों में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी शक्तियां जोर पकड़ रही हैं, जो हिंसा में विश्वास करती हैं, जो विध्वंस में विश्वास करती हैं और जो हथियार लेकर गणतंत्र से लड़ने की तैयारी करते हैं। उनका मुकाबला किया जा रहा है। लेकिन राज्यों के सीमित साधन हैं, उन साधनों को बढ़ाने की भी कोशिश होती है। राज्यों के संबंध में सम्मेलन भी हुए हैं। नेपाल से लेकर आंध्र तक एक ऐसी रेखा खींचा जा सकती है जिसमें कई प्रदेशों के क्षेत्र समाविष्ट होते हैं जो उद्वेलित हैं, उद्विग्न हैं, आंदोलित हैं और हिंसात्मक आंदोलन की ओर प्रेरित हो रहे हैं। पुलिस को मुठभेड़ में मारा जाता है। उन पुलिसवालों के घर वालों का क्या होगा? उन पुलिस वालों को तो हम उतनी सुविधाएं भी नहीं दे पाते हैं जितनी कि अन्य पुलिस दलों के लोगों को मिलती हैं। लेकिन मामला केवल पुलिस का नहीं है। इसके लिए सब मिलकर

बैठें, विचार करें, इसकी आवश्यकता है। पड़ौसी नेपाल में क्या हुआ, क्या हो रहा है ? हमारे लिए चेतावनी है। देश के भीतर हिंसा बढ़े, हथियार लेकर चलने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले और येंन-केन-प्रकारेण सत्ता हथिया ली जाए, इस तरह की हवा बने, तो यह देश की शांति के लिए ठीक नहीं है, देश के भविष्य के लिए ठीक नही है, इस पर सारे सदन को, सारे देश को गंभीरता से विचार करना होगा। मामला केवल पुलिस का नहीं है, यह भी देखना होगा कि उन क्षेत्रो में विकास की रफ्तार क्या है। क्या ये आदिवासी क्षेत्र और पिछड़ गए हैं ? क्या सशस्त्र संघर्ष के कारण उनके विकास में और कठिनाइयां पैदा हो गई हैं? उनके लिए विकास का कौन सा ढांचा तैयार किया जाय। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं डा. मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होने इस समस्या की ओर सारे सदन का ध्यान खीचा है।

राष्ट्रपति जी के भाषण मे अयोध्या का भी उल्लेख है। यह पहली बार नही है। पिछले साल भी जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, उसमें अयोध्या का उल्लेख था। प्रारम्भ से हमारी भूमिका रही है कि विवाद बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है , इसको हल किया जाना चाहिए। हल करने के दो ही तरीके हैं। आपस की बातचीत से हल किया जाए, सदभावना से हल किया जाए और दूसरा रास्ता यह है कि अदालत का फैसला माना जाए। अदालत में देर लगती है यह बात सच है। यहां बड़े-बड़े वकील बैठे हैं, वे कोई ऐसा रास्ता बतायें जिससे जल्दी मे सुनवाई हो सके, फैसला हो सके, अपराधियो को दंड दिया जा सके या ऐसा फैसला हो कि उसको खोल दिया जाए। वह भी समझ में आ सकता है। लेकिन देर लगती है। इसीलिए केन्द्र सरकार कोर्ट मे गई, सुप्रीम कोर्ट में गई। जो जमीन का मामला है, जो अविवादित जमीन है, इसके बारे में कोर्ट ने पहले भी फैसला दे दिया है। आप उसको जल्दी से तय कर दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु : फैसला नही होने से कैसे होगा ? ...**(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह किसी राजनैतिक उद्देश्य से नही किया गया है । ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु : फैसला नही होने से संभव नही होगा । ...**(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब तारीख तय हो गयी है । ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है । ...**(व्यवधान)**... पार्लियामेंट का कानून चैलेंज हुआ है । सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया । ...**(व्यवधान)**...

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ (Madhya Pradesh): Madam, it is totally politically motivated; this is not fair. ...*(Interruptions)*... It is unfortunate that you are guided by certain communal forces in the BJP. ...*(Interruptions)*... You are cowed down by these forces. These communal forces are misleading you. ...*(Interruptions)*...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदया, तारीख तय हो गयी है । उस तारीख की हम प्रतीक्षा करे । ...**(व्यवधान)**... अपने-अपने पक्ष को रखे । ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल (बिहार) : उसको केन्द्र सरकार ने सपोर्ट किया है । ...**(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम इंतजार करे । इस सवाल को लेकर साम्प्रदायिकता भड़के, इसका कोई कारण नहीं है । ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु : वी.एच.पी. को समझाइए । ...**(व्यवधान)**... वे तो त्रिशूल का बंटवारा कर रहे हैं । वे तो देश में त्रिशूल बांट रहे हैं । ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस.अहलुवालिया (झारखंड) : मैडम, यह क्या है ? यह भी जरा समझ लो । ...**(व्यवधान)**... ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब यहीं हम ठीक तरह से चर्चा नहीं कर पा रहे तो बाहर क्या होगा ?

श्री नीलोत्पल बसु : तोगड़िया जहां पर है । ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Order, please. ...*(Interruptions)*...

श्री कपिल सिब्बल : बाहर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं । ...**(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर कोई व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करता है, सीमा लांघता है तो उसके लिए कानून है । ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल : त्रिशूल बांटता है ...**(व्यवधान)**...

श्री शाहिद सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश) : सबके लिए कानून होना चाहिए । तोगड़िया के लिए भी कानून होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Order, please. ...*(Interruptions)*... आप बैठिए । बैठ जाइए ।

प्रो. राम देव भंडारी (बिहार) : तोगड़िया को ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Order. Please take your seats. Take your seats. ...*(Interruptions)*... Please take your seats. Sit down. ...*(Interruptions)*... Sit down. ...*(Interruptions)*... बैठिए । बैठ जाइए । ...**(व्यवधान)**...

अहलुवालिया जी, आप भी बैठ जाइए ।

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Find out how he has killed all the Muslims. ...*(Interruptions)*... It is his statement that he is going to remove Islam from the country. ...*(Interruptions)*...

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (मध्य प्रदेश): नफरत पैदा करने वालों को ...**(व्यवधान)**...

SHRI JANARDHANA POOJARY : That is his statement. You kindly read it. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please take your seat, Mr. Poojary. ...*(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY : He has admitted he has killed. ...*(Interruptions)*... This is the statement of ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please take your seat, Mr. Poojary.

SHRI JANARDHANA POOJARY : Tell us what action, as the Prime Minister, you have taken. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह क्या कह रहे हैं ? ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Just one minute. Please take your seats. ...*(Interruptions)*...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने यील्ड नही किया है । ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : बैठिए । आप बैठ जाइए । I want to tell the Members that we have 494 amendments. ...*(Interruptions)*... No, I am not allowing it. ...*(Interruptions)*... There are 494 amendments. ...*(Interruptions)*... Please sit down. There are 494 amendments which have to be voted and cleared. If you are not willing to listen to him, and only interrupt then we will have to sit in the lunch hour. ...*(Interruptions)*...

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश) : हम यह कह रहे हैं कि...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : आप यह क्या कर रहे हैं ? यह इंटरप्शन नहीं तो क्या है ? ...**(व्यवधान)**...

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी : हम सवाल पूछ रहे हैं ।

उपसभापति : वही इंटरप्शन होता है । भाषण के बीच में बोलना इंटरप्शन ही होता है । Please sit down. Take your seats. ...*(Interruptions)*... Please take your seats. ...*(Interruption)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

SHRI JIBON ROY (West Bengal): The Government should be able to control uncivilised elements in the BJP. ...*(Interruptions)*...

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी : मैडम, हम प्रधानमंत्री जी की कद्र करते हैं मगर जो लोग सद्भावना तोड़ते हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ? ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : प्लीज़ आप बैठिए । Don't do this.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Goa): Is Mr. Togadia not a terrorist? ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Order. ...*(Interruptions)*... बैठिए । प्लीज़ बैठिए । Let us finish. Don't do this; otherwise, you will have to sit through 494 amendments. I am just telling you. ....*(Interruptions)*... Please let me finish.

प्रो. सैफुद्दीन सोज (जम्मू और कश्मीर) : मैडम ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : सोज साहब, आप बैठिए । ...**(व्यवधान)**... Mr. Soz, please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री के. रहमान खान (कर्नाटक) : मैडम, ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : रहमान साहब, आप भी बैठिए ।

SHRI JIBON ROY : The Prime Minister is too weak to control some uncivilised elements in his party. Unless they are controlled, nothing will happen.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*...

Dr. ABRAR AHMED (Rajasthan) :

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Abrar Ahmed, how many times I should tell you? ...*(Interruptions)*... Please don't get up. This is known as interruption.

श्री जीवन राय :*

SHRI NILOTPAL BASU :*

SHRI EDUARDO FALEIRO :*

THE DEPUTY CHAIRMAN : Order. ...*(Interruptions)*... Please sit down. What is this happening to the House when the Prime Minister is replying? You wanted him to reply, and whatever he is replying, it is his reply; it is not your reply. What he replies, he replies. So, please listen to him. ...*(Interruptions)*... Just listen ...*(Interruptions)*...

SHRI JIBON ROY : We are bringing out here...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : बैठ जाइए, Please, sit down. ...*(Interruptions)*... बैठिए.....पी.एम. साहब बोलिए। अब कोई आवाज़ नहीं करेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण मे जो कहा गया है, उसी को मैं दोहरा रहा हूं। मैं कोई अनहोनी बात नही कह रहा हूं। राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण मे कहा था कि मेरी सरकार ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि अयोध्या विवाद को या तो दोनों समुदायो के मध्य वार्ता द्वारा सुलझाया जा सकता है अथवा न्यायपालिका के निर्णय द्वारा, जिसे सभी संबंधितो को मानना होगा। ...**(व्यवधान)**...

कुछ माननीय सदस्य : मानना होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : न्यायपालिका को ...**(व्यवधान)**... और सुनिए ...**(व्यवधान)**... सुनते जाइए। मुझे बोलने का अवसर दिया गया है। ...**(व्यवधान)**...

---

*Not recorded.

SHRI RAJU PARMAR (Gujarat) : Once you have said ...*(Interruptions)*...

SHRI JIBON ROY : The Prime Minister is ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please, sit down ...*(Interruptions)*... बैठ जाइए । ...**(व्यवधान)**... सोज़ साहब, यह आपको शोभा नहीं देता, आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदया, मैं अपने बोलने के अधिकार का आपसे संरक्षण चाहता हूं। इस सदन में मुझे बोलने का अधिकार है या नहीं?

उपसभापति : आपको अधिकार है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर ये इसी तरह से शोरगुल मचाते रहे तो ..**(व्यवधान)**...

जीवन राय : दो-दो आदमियों को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए । ...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम देव भंडारी : सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : देखिए, आपको भी यह शोभा नहीं देता और किसी को भी शोभा नहीं देता कि जब आपका समय आइडेंटिफाई नहीं किया गया है तब आप बोलें। प्रधानमंत्री जी को अपना भाषण खत्म करने दीजिए। मैंने आपको कहा है कि 494 अमेंडमेंट्स हैं and I will sit through all the amendments, to vote or to move. So, please be quiet. Let him finish his speech. ...*(Interruptions)*... Shri Abrar Ahmed, what is this? बैठिए, अभी मैंने आपको कहा कि बैठ जाइए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप फौरन खड़े हो जाएंगे and I did not tell you to get up. So, please sit down and listen. Mr. Togadia is not a Member of this House. So, I am not going to mention anything on him. ...*(Interruptions)*... I have to appeal to you first ...*(Interruptions)*... All those people who are not Members of the House should not be mentioned. ...*(Interruptions)*... चलिए, बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... प्रधानमंत्री जी बोलिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदया, मैं दूसरे मुद्दे पर आना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN : No comments are needed, please. When Mr. Manmohan Singh was speaking, nobody interrupted. Why can't you just sit and listen to the speech? Do you believe in democracy or not?

...*(Interruptions)*... प्रधान मंत्री जी बोलिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदया, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं इसलिए चुप बैठते हैं । महोदया, मैं एक और मुद्दा उठाना चाहता हूं और वह मुद्दा है महिलाओं के आरक्षण का।

उपसभापति : अब तो सुन लीजिए, आरक्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अधिकांश पार्टियां इससे प्रतिबद्ध हैं कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले संसद में, विधान मंडल में। इससे ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरोज दुबे : महोदया.....

उपसभापति : अच्छा, अब आप क्यों बोल रही हैं? बैठिए। उन्हें बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... अगर आप इस तरह से ...**(व्यवधान)**... बैठिए, बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए। देखिए, महिलाओं के आरक्षण की बात है। अगर महिलाएं इस पर शोर मचाएंगी तो फिर बाहर लोग कहेंगे कि इतनी महिलाएं थीं तो इतना शोर मच रहा है, इनको मत दो। ...**(व्यवधान)**... अपनी कास्ट को खराब मत करिए। शांति से सुनिए, अपने कास्ट को मत बिगाड़िए। ...**(व्यवधान)**... बोलिए प्रधानमंत्री साहब। ...**(व्यवधान)**... आप दे रहे हैं सजेशन्स ...**(व्यवधान)**...

श्री लालू प्रसाद : माननीय प्रधानमंत्री तो महिला विरोधी हैं, आज तक इन्होंने शादी नहीं की है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : लालू जी, यह तो मालूम है कि आप महिलाओं के हित में हैं, तभी तो आपने यहां महिला को मुख्य मंत्री बना दिया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री लालू प्रसाद : शाहजहां ने तो बेगम के मरने के बाद ताजमहल बनाया था, हमने अपनी बीवी के जीते जी ताजमहल बना दिया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदया, मुझे विश्वास है कि महिला आरक्षण के बारे में एक सर्वानुमति होगी और इसी सत्र में एक राय बन जाए, विधेयक पेश हो जाए और हम यहां से महिला आरक्षण का निर्णय करके वापस जाएं ...**(व्यवधान)**... धन्यवाद ।

उपसभापति : अभी हो गया है। ...**(व्यवधान)**... आप लोग बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... अभी महिला आरक्षण की बात पर सब लोग तैयार हैं, फिर क्या झगड़ा है? ...**(व्यवधान)**... कोई जरूरी नहीं है कि हम जोर से बोलें। ...**(व्यवधान)**... I am not allowing. ...*(Interruptions)*... Nothing is allowed. ...*(Interruptions)*... No...*(Interruptions)*... अभी महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है, आप उसको बिगाड़िए मत। ...**(व्यवधान)**... Don't destroy the Women's Bill. ...*(Interruptions)*... Please sit down. हो गया गंभीर मामला। बैठ जाइए। बैठिए, बैठिए। ...**(व्यवधान)**... महिलाओं का आरक्षण भी गंभीर है, बैठ

1.00 p.m.

जाइए। बैठ जाइए। आप बैठेंगे तो वे बोलेंगे। बैठ जाइए। ...*(Interruptions)*... No ...*(Interruptions)*... I am not allowing anything now. ...*(Interruptions)*... No ...*(Interruptions)*... Okay. ...*(Interruptions)*... All right. ...*(Interruptions)*... I heard it. ...*(Interruptions)*... I am not allowing. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Mr. Pachouri, I am not allowing. ...*(Interruptions)*... I am not allowing anything. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Mr.Suresh Pachouri, please sit down. ...*(Interrupitons)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... I am not allowing. ...*(Interruptions)*... No. ...*(Interruptions)*... Don't shout. ...*(Interruptions)*... Don't shout. ...*(Interruptions)*... Mr. Pachouri, don't raise your voice. ...*(Interruptions)*... I think you know it very well. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARJUN SINGH (Madhya Pradesh) : Madam, I would like to know whether his speech is over. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Yes, his speech is over, I am told. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARJUN SINGH : Then we have a right to seek certain clarifications. ...*(Interruptions)*...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh) : Madam, then we should be permitted to seek some clarifications. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Prime Minister, is your speech over? ...*(Interruptions)*... मुझे सुनने दीजिए ...**(व्यवधान)**... I can't hear him. ...*(Interruptions)*... Let me hear him. ...*(Interruptions)*... अच्छा आप एक मिनट बैठेंगे? यह जानने दीजिए कि यह भाषण खत्म हो गया या नहीं हुआ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदया, मैं और भी कुछ मुद्दे उठाना चाहता था। ...**(व्यवधान)**... लेकिन अगर मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा तो मैं कैसे बोलूंगा?

उपसभापति : बोलने दीजिए। ऐसा मत करिए। Don't interrupt, please.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जिन प्रश्नों को माननीय सदस्यों ने उठाया है उनमें अभाव के कारण उत्पन्न स्थिति भी है। अन्न का अभाव है । राजस्थान की स्थिति विकराल है । सबसे अधिक बुरी है और इसीलिए हमने राजस्थान को सबसे अधिक धन दिया है ।

श्री सुरेश पचौरी : जितना मांगा है, उतना नहीं दिया है, प्रधानमंत्री जी ने ।

उपसभापति : सुनिए ...**(व्यवधान)**... सुरेश पचौरी जी बैठिए ...**(व्यवधान)**... Let him speak. That is not the way. It is unbecoming of you, at least.

श्री सुरेश पचौरी : यह मेरा अधिकार है ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : बैठिए, बैठिए ...**(व्यवधान)**... Let him complete. This is not done in this House.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपसभापति जी, यह आंकड़ों का सवाल है, तथ्यों को देखा जा सकता है ...**(व्यवधान)**... जो माननीय सदस्य राजस्थान में रुचि रखते हैं, राजस्थान की व्यथा से पीड़ित हैं, वे मुझसे मिल लें । मैं उनकी बैठक अलग कर लूंगा । मैं राजस्थान की सरकार के प्रतिनिधियों को भी बुलाने के लिए तैयार हूं ...**(व्यवधान)**...

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान) : ठीक है, आप समय दीजिए ...**(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम बैठकर यह मामला तय कर लें । अभी नई फसल आने वाली है । उसके बाद भी जिन प्रदेशों में सूखा रहेगा वहां विकट स्थिति बनने वाली है। पीने के पानी का संकट पैदा होगा । चारे की कमी है अभी । इस सदन को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा लेकिन प्राथमिकताएं आप तय कर लीजिए । हम राजस्थान पर अलग से चर्चा के लिए तैयार हैं या पूरे सूखे के सवाल पर चर्चा के लिए तैयार हैं ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Prime Minister, we had a discussion on *sookha* in this House in this Session itself. And I tell you that there was a *sookha* in this House also as there were very few Members present.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH : Madam, the discussion took place in the last Session. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : No, no. The discussion took place in this Session itself.

उपसभापति : आप बैठिए, आप बैठिए ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रेम गुप्ता (बिहार) : मान्यवर, बाढ़ को भी इन्क्लूड कर लीजिए ...**(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : .... हम चर्चा कर सकते हैं । अगर सदस्यो की राय हो, सदन चाहे तो इस पर फिर से चर्चा हो सकती है ...**(व्यवधान)**... अगर बिना चर्चा के आप तथ्यो को जानना चाहते हैं तो मेरा निवेदन यह है कि पहले आप तथ्यों को जान ले ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Order please. Order.

श्री प्रेम गुप्ता : बाढ़ को भी इन्क्लूड कर लीजिए ...**(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अलग चर्चा हो जाएगी ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : बैठिए, बैठिए ...**(व्यवधान)**... आपके कहने पर ही चर्चा हुई थी It was your Motion on which we had the discussion. ...*(Interruptions)*... आप बैठिए, आप बैठिए ...**(व्यवधान)**...

डा. अबरार अहमद : पीने के पानी के लिए बारह करोड़ रुपए दिए हैं ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN : If you are going to continue on every question like this, then we cannot finish it till 5 o' clock. We will go on sitting, everybody will go on sitting.

श्री सुरेश पचौरी : घोषणा की है कि खाद्यान्न की कमी नही होगी लेकिन अभी-भी खाद्यान्न की कमी है । वही राजस्थान है, वही झारखण्ड है । अन्य सूखाग्रस्त राज्य हैं ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : आप मीटिंग बुला लीजिए बैठिए ...**(व्यवधान)**... बस अब हो गया । Now, it is done. मीटिंग हो जाएगी ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरोज दुबे : बिहार कभी दिखता ही नहीं है ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है ...**(व्यवधान)**...

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी : ठीक है, आप मीटिंग बुलवा लीजिए ...**(व्यवधान)**...

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : ठीक है, आप बुलवा लीजिए ...**(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां, लेकिन मीटिंग मे लोगों को आना चाहिए ।

श्री मूल चन्द मीणा : जरूर आएंगे ...**(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदया, मैं एक मामले की तरफ और इशारा करना चाहता था और वह है देश के भीतर हुए प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन के बारे में । भारत के बाहर बड़ी संख्या मे भारतीय रहते हैं । भारतवंशी हैं । रोजगार की तलाश में गए हैं । अपना भविष्य बनाने में सफल हुए हैं । आज उनका दुनिया मे स्थान है । अपने-अपने देश में स्थान है । मगर उनकी कठिनाइयां भी हैं। उनकी समस्याएं हैं और पहली बार हमने एकत्र होकर उनके सम्मेलन में उनकी कठिनाइयों पर विचार किया और उनको हल करने का रास्ता निकाला । वह सम्मेलन किसी दल से संबंधित नहीं था । वह सर्वदलीय सम्मेलन था । उसमें जो निर्णय किए गए हैं उन्हे सरकार को कार्यान्वित करना है । हम कुछ देशों के साथ दोहरी नागरिकता अपनाने पर भी विचार कर रहे हैं । लेकिन उद्देश्य एक ही है कि विदेशों में जो भारतीय बसे हुए हैं, वे अपने-अपने देशों के प्रति अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए सांस्कृतिक आधार पर भारत के साथ मेल-जोल रखें, मेल-जोल बढ़ाएं और विश्व में भाईचारा बढे । इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं । सब लोगों ने इसमें सहयोग दिया था, इसके लिए हम उन्हे धन्यवाद दे चुके हैं । मैं इसका उल्लेख करना जरूरी समझता था, खासकर डा. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी का, जिन्होंने आगे बढ़ कर इस सम्मेलन के आयोजन मे भाग लिया । यह सम्मेलन, आगे आवश्यकता हुई, तो फिर आपको सूचना दे कर किया जाएगा । धन्यवाद ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I shall now put the amendments, which have been moved, to vote. Amendment Nos. 1 to 11 moved by Dr. Abrar Ahmed. Are you withdrawing your amendments?

DR. ABRAR AHMED : Madam, I withdraw my amendments.

Amendment Nos. 1 to 11 were, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now I take up Amendment Nos. 12 to 18 moved by Prof. Saif-ud-Din Soz. Are you withdrawing your amendments?

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ : I will withdraw all my amendments, but before that I would like to speak for two-three minutes because I have not spoken on this earlier.

Earlier, when there was a row here, I wanted to say that we hold the Prime Minister in high esteem. When he said that there was rule of law, some of us raised a question, "How is Togadia? Why isn't he being seen as a campaigner of hate?" He has not been arraigned anywhere. He has not been stopped. That was a limited interruption. But I want to say something on Kashmir. The Prime Minister's head and heart are in place. I accept that his intentions with regard to Kashmir are correct. But I would

like to raise a question. The President of India said - it is laudable - that the people of Kashmir have participated in elections. They faced so many odds and threats to their lives. The President talked of free and fair elections there. The international community had accepted these elections. The Prime Minister's intentions are known to me personally. But we must see how the Government of India is operating in this process and how it is reacting to the situation. I feel that the policy of the Government of India in regard to Kashmir is not cohesive. It is an *ad hoc* policy. I want a qualitative change in that policy. Even my amendments relate to the aspirations of the people. What is the Government doing to take into consideration the aspirations of the people of Jammu and Kashmir? Recently, they appointed Shri Vohra. But there are no terms of reference. Perhaps, the Deputy Prime Minister responded to the discussion half-heartedly. The name of Shri Vohra was also mentioned. I raised a question, "What are the terms of reference?" He cannot be allowed to be an unguided missile. He must do things in Kashmir differently from what Shri Pant did earlier. There should be a vigorous dialogue with the representatives of the people, with the other opinion leaders.

So far as development of Jammu and Kashmir is concerned, I would like to put a question to the hon. Prime Minister. Jammu and Kashmir is not on the industrial map of India. Even the tiny HMT unit is now defunct. What is the Government of India doing by way of development? So far as development is concerned, they must bring Jammu and Kashmir on the industrial map of India. What has been done in regard to pollution free industries and the electronics industry?

Now I come to the Railways. The Prime Minister has said that a railway line would go to Srinagar. I must remind him that it should go to Baramulla as was approved earlier. Unless they do it as a separate item in the General Budget, like the Government of India did in the case of the Konkan Railways, it cannot come up. We have not been able to take the railway line up to Udhampur in the last 25 years. How can the Prime Minister say that he would take the railway line to Baramulla or Srinagar by 2007? I request the Prime Minister to respond to the situation. Take the railway line there and get Jammu and Kashmir on the industrial map of India. The Prime Minister must respond to it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are you withdrawing your amendments?

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ : Madam, kindly urge the Government of India to respond to the situation. I withdraw my amendments.

Amendments No:12-18 were, by leave, withdrawn

THE DEPUTY CHAIRMAN : Amendments No:95-135 and 494 by Shri Kapil Sibal.

SHRI SURESH PACHOURI : Madam, I also have some amendments.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Yes, it is coming. All are listed.

SHRI KAPIL SIBAL : Madam, as far as amendments no: 95-135 are concerned, I beg to withdraw. As far as amendment no: 494 is concerned, this amendment relates to POTA. Madam, I just want to mention that we have another amendment no:481, which also relates to POTA. We will deal with that separately with the permission of the Chair.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal) : Madam, we will deal with that later if you permit. Both these amendments relate to POTA and we can deal with them together.

SHRI KAPIL SIBAL : So, 494 and 481 can be dealt with later.

THE DEPUTY CHAIRMAN : So, when it comes to amendment no: 481, we will deal amendment no: 494 alongwith it.

Amendments No:95-135 were, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now, amendments No:136-168 by Shri Ramachandra Khuntia.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA (Orissa) : Madam, I want to say something briefly.

THE DEPUTY CHAIRMAN : It should be only on the amendments.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA : Madam, I just want to mention

that the Prime Minister, in his reply, has not said anything about the employment generation, employment protection and employment opportunities for unemployed youth. Unemployment is also being created by the VRS, downsizing and rightsizing the workers. The Prime Minister has also not said anything by way of modernisation, upgradation. Ninety per cent of the organised and unorganised workers are now becoming unemployed because there is no skill upgradation and the Government has no funds, no action plan for the upgradation of their skill and if their skill is not upgraded, these women, Scheduled Caste, Scheduled Tribe people will be rendered unemployed for a long time. I would like to say one more thing about Orissa KBK district. The State Government of Orissa has sent an action plan, long-term action plan, which has also not been approved by this Government till now. And, the Prime Minister has not said anything regarding that and also in Orissa, after the super-cyclone, floods and recent floods, people are dying. There is an allegation of starvation deaths. Still, nothing has been said. Nothing has been done about how to deal with Orissa situation. I think, if it is clear, I would withdraw all my amendments.

Amendments No:136-168 were, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN : A very feeble response to it. Now, amendments no:233-268 by Shri J.Chitharanjan.

SHRI J.CHITHARANJAN (Kerala) : Madam, I may withdraw all my amendments, except amendment no:234, for which I would like to press.

THE DEPUTY CHAIRMAN : So, let me get the other amendments withdrawn. Then, you can speak.

Amendment No:233 and 235-268 were, by leave, withdrawn

THE DEPUTY CHAIRMAN : Amendment No. 234, Mr. Chitharanjan:

SHRI J.CHITHARANJAN : Madam, my amendment is :

That at the end of the Motion, following be added, namely :

"but regret that the Address does not express its concern over the steep fall in the agricultural produce, including cash crops, like rubber, tea,

coffee, cotton, etc., resulting in severe losses and indebtedness to millions of farmers all over the country. I urge upon the Government to take immediate and necessary steps to relieve the farmers from their miserable plight."

Madam Deputy Chairperson, you see, this is a problem, which the entire nation was concerned about for the last several years, 3-4 years. The prices of almost all the agricultural commodities have fallen. And, because of that, the millions of farmers in our country are facing very heavy losses and they also get severely indebted. This has created a desperate situation on the agrarian front and hundreds of families, who have become so desperate that they have begun to commit suicides. Not only individuals, but also all the members of their families, have begun to commit suicides. In such a situation, no proper solution for it has been mentioned in the President's Address. This has not been taken seriously...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Do you want to press it or you want to withdraw it?

SHRI J. CHITHARANJAN : I want to move my amendment, No.234.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I now put Amendment No.234 to vote.

Amendment, No.234, was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I will now take up Amendment Nos. 269 to 280. Shri Prasanta Chatterjee, are you pressing the amendments?

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal) : I am not pressing my amendments. But there are certain important issues which I want to highlight here. There is no mention about the fiscal demands of the State Government. There is no mention about communal tensions and atrocities on minorities in Gujarat. There is also no mention of the Reports of the Minority Commission and Human Rights Commission. Madam, I am not pressing my amendments, but these are very important issues.

Amendment Nos. 269 to 280 were, by leave, withdrawn

THE DEPUTY CHAIRMAN : I will now take up amendment Nos. 281 to 311 by Shri Balkavi Bairagi. Are you pressing your amendments?

श्री बालकवि बैरागी : मैडम,...

उपसभापति : अब यह भाषण करने का कोई नया तरीका है?

श्री बालकवि बैरागी : मैडम ! भाषण का सवाल नहीं है, मुझे प्रधानमंत्री महोदय से कुल तीन वाक्यों में तीन बात कहनी हैं। एक तो इस पूरे अभिभाषण में कहीं पर गांधी शब्द का उल्लेख नही हुआ। गांधीनगर का उल्लेख है, गांधी शब्द तक का भी उल्लेख नही है। ...**(व्यवधान)**... मैं सारे गांधी की बात कर रहा हूँ, जिस गांधी को भी आप मानते हो। दूसरा, इस पूरे अभिभाषण मे माननीय प्रधानमंत्री जी कही पर भी स्वदेशी शब्द का उल्लेख भी नही है और तीसरा, हिन्दी के पदो को भरने के लिए आपने इस देश मे कोई गुंजाइश नही छोड़ी। राजभाषा विभाग कहता है कि हिन्दी के पद भरे जाएंगे, लेकिन वित्त मंत्रालय कहता है कि नही भरे जाएंगे। इसका निर्णय, इसका फैसला, आप चूंकि उस कमेटी मे रह चुके हैं और इस देश के रहनुमा हैं इसलिए आपको करना है। इन तीनों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं अपने सारे अमेंडमेंट वापस लेता हूँ।

Amendment Nos. 281 to 311 were, by leave, withdrawn

उपसभापति : अमेंडमेंट नंबर 312 से 315, **प्रो0 रामगोपाल यादव** जी। आप तो विदड्रा कर लीजिए।

प्रो. रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : मैडम, जो आपका हुकुम होगा, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो मेरा अमेंडमेंट है नंबर 312, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विरोधी दल के लोगो का उत्पीड़न किया जा रहा है और आप लोग सहयोग कर रहे हैं उस सरकार को, आपने राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में उसकी निंदा के लिए कुछ भी नहीं लिखवाया है। यह बहुत खराब बात है। इतना कहकर मैं अपने सारे अमेंडमेंट विदड्रा करता हूँ।

Amendment Nos. 312 to 315 were, by leave, withdrawn

THE DEPUTY CHAIRMAN : I will now take up amendment Nos. 316 to 355. Shri Suresh Pachouri, are you pressing your amendments?

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, मैं केवल अपने जो संशोधन क्रमांक 330 और 332 हैं, उनका उल्लेख आपके जरिए करना चाहूंगा और प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपने अपने उत्तर में सूखा प्रभावित राज्यो के संबंध मे कुछ बाते कही हैं, लेकिन जहां तक खाद्यान्न के उपलब्ध कराने की बात है आपने स्वयं इस हाऊस मे यह कहा था कि इन राज्यों मे खाद्यान्न की किसी भी हालत में कमी नही रहने दी जाएगी। राजस्थान का उल्लेख यहां किया गया कि 42 लाख टन खाद्यान्न की मांग की गई है, लेकिन 21 लाख टन ही उपलब्ध कराया गया और खाद्यान्न के आवंटन मे भी बंधन लगाए गए हैं, इनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक बंधन यह है कि मात्र खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 50

प्रतिशत परिवार हैं उनको कवर किया जाएगा और एक परिवार से केवल एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा, वह भी माह में केवल दस दिन। क्या उसमें आप कुछ शिथिलता बरतेंगे क्योंकि अधिकांश राज्य सूखा प्रभावित हैं? यह मैं आपके जरिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा।

महोदया, जहां तक मेरे बाकी संशोधनों का प्रश्न है, तो मैं यह कहना चाहूंगा बड़े अदब के साथ प्रधानमंत्री जी से, कि दूसरा घर आपका हिमाचल प्रदेश ढह चुका है, पहला घर जो उत्तर प्रदेश है वहां माया बैठ चुकी है, इसलिए आपकी व्यथा को समझते हुए मैं आपको और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहता और इसलिए अपने सारे संशोधन वापस लेता हूँ।

Amendment Nos. 316 to 355 were, by leave, withdrawn

उपसभापति : Amendment Nos. 375 to 391 by **श्रीमती सरोज दुबे** । आप तो विदड्रा करेंगी।

श्रीमती सरोज दुबे : मैडम, 375 से 391 तक मेरे अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन 381 को प्रैस करना चाहती हूं ।

उपसभापति महोदया, बिहार के विभाजन के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि बिहार के आर्थिक विकास के लिए एक आर्थिक पैकेज देंगे 1,87,000 करोड़ रुपए का, लेकिन लम्बा समय गुजर गया परन्तु आज तक उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई । यह वादाखिलाफी यह जाहिर करती है कि यह सरकार दलित विरोधी है, किसान विरोधी है और गरीब महिलाओं की भी विरोधी है। यह पैकेज अविलम्ब दिया जाना चाहिए क्योंकि बिहार कभी सूखे से जूझता है, कभी बाढ़ से जूझता है और बिहार के सारे प्राकृतिक संसाधन विभाजन के समय झारखंड में चले गए हैं। तो मैं ये आश्वासन चाहती हूं प्रधानमंत्री जी से कि आज वे सदन में आश्वासन दें कि बिहार का आर्थिक पैकेज एक नियमित समय के अंदर दे देंगे, तभी मैं इसको वापिस ले सकती हूं वरना मैं इसे वापिस नहीं लूंगी ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Do you want to withdraw it or shall I put it to vote?

श्री लालू प्रसाद : मैडम, प्रधानमंत्री ने बिहार बंटवारे के समय यह वादा किया था कि हम कोई तकलीफ नहीं होने देंगे और एक आर्थिक पैकेज देंगे । आपने इस पर पहल भी की थी, आल पार्टी मीटिंग की, मुख्य मंत्री और सभी लोग आए । तो कम से कम आश्वासन दे देना चाहिए आपको ।

श्रीमती सरोज दुबे : आज आश्वासन दे ही दीजिए आप ।

उपसभापति : चलिए, आप विदड्रा कर रही हैं या मैं वोट के लिए मूव करूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I am putting Amendment Nos. 375 to 391 to vote. ...*(Interruptions)*... My job is either to get the amendments withdrawn, or, if you do not withdraw them, to put them to vote. Do you want to press them? I cannot get you the assurance. ...*(Interruptions)*...

श्री लालू प्रसाद : मैडम, प्रधानमंत्री जी को आश्वासन देना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरोज दुबे : हम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि आप बिहार की गरीब जनता के लिए कुछ तो कर दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Shall I put Amendment Nos. 375 to 391 to vote?

श्री लालू प्रसाद : मैडम, प्रधानमंत्री जी बिहार के पैकेज के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन तो लिया जाए।

उपसभापति : अभी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है। सरोज जी, आप विदड्रा कर रही हैं या मैं वोट के लिए मूव करूं ? ...**(व्यवधान)**...

श्री लालू प्रसाद : या यही कह दीजिए कि नही दे रहे हैं तो बात स्पष्ट हो जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरोज दुबे : कुछ तो कह दीजिए। प्रधानमंत्री जी, कुछ तो कहें। ...**(व्यवधान)**... कुछ तो बोल दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ तो कहिए।

उपसभापति : सरोज जी, आप विदड्रा कर रही हैं या नहीं?

श्रीमती सरोज दुबे : मैडम, मैं विदड्रा नहीं कर रही। Then, I shall put them to vote.

श्री लालू प्रसाद : मैडम, इनके केन्द्रीय मंत्री वहां जाकर विकास-विकास की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी बोले थे। आज इस पर वोट हो जाए, यह स्पष्ट हो जाए कि बिहार के प्रति इनका क्या दर्द है।

श्रीमती सरोज दुबे : बिहार के साथ सौतेला व्यवहार होता है।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Are you withdrawing them or shall I put them to vote?

श्रीमती सरोज दुबे : नही, मैं विदड्रा नही कर रही हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN : All right. I am putting Amendment Nos. 375 to 391 to vote.

Amendment Nos. 375 to 391 were negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Do you want a division? ...*(Interruptions)*... Amendment Nos.392 to 405 by Shrimati Sarla Maheshwari. ...*(Interruptions)*...

श्री लालू प्रसाद : मैडम, इधर की जीत हुई है, डिवीजन कराइए ।

एक माननीय सदस्य : डिवीज़न कराइए मैडम।

उपसभापति : जब मैंने बोला था, आपने उस वक्त नही कहा।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभापति महोदया, मेरे संशोधन क्रमांक 392 से 405 हैं और मैं एक संशोधन क्रमांक 394 को छोड़कर बाकी सबको वापिस लेने के लिए सहमत हूं। मैं उसे यहां पर दोहराना चाहूंगी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगी और आपके माध्यम से इस संशोधन पर प्रधानमंत्री जी से एक बार फिर आश्वासन चाहूंगी कि कृपया सिर्फ वादा मत करिए क्योंकि वादो की चूसनी चूसते-चूसते हमारी जीभ पर छाले पड़ गए हैं और यह चूसनी और चूसने की हमारे में ताक़त नही है, इसलिए इस वादे को आप निभाएं।

उपसभापति महोदया, मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है, किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि महिलाओ के सशक्तिकरण हेतु, उनके आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों के प्रति सरकार गंभीर है। विधान सभाओ तथा लोक सभा मे महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटे आरक्षित करवाने हेतु विधेयक पारित करवाने के प्रति भी सरकार गंभीर नही है। उपसभापति महोदया, मैं चाहूंगी कि आप कृपया हम सब की तरफ से, इस सदन की तरफ से प्रधानमंत्री जी से यह कहिए कि सिर्फ वायदा न करे और इस सदन में इसको पास कराएं।

उपसभापति : आप गालिब का एक शेर सुनना चाहेगी इस वायदे के ऊपर?

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैडम, इस वायदे पर आप ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : वही मैं बोल रही हूं। गालिब ने एक शेर कहा है :

"तेरे वायदे पे जिएं हम, तो यह जान जाने जाना,
कि खुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता।"

श्रीमती सरला माहेश्वरी : हमें खुशी से मरना कबूल है। कम से कम वह मौत तो दीजिए।

उपसभापति : प्रधानमंत्री को मैसेज चला गया। So, you withdraw your amendments.

SHRIMATI SARLA MAHESHWARI : Yes, Madam. I withdraw my amendments.

Amendments (Nos. 392 to 405) were, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN : We now take up Amendment Nos. 406 to 417, moved by Shri S. Ramachandran Pillai. Mr. Pillai, are you pressing?

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala) : No, Madam. I withdraw my amendments.

Amendments (No. 406 to 417) were, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN : We now take up Amendment Nos. 418 to 421 by Shri C. O. Poulose. Mr. Poulose, are you pressing?

SHRI C. O. POULOSE (Kerala) : Madam, I withdraw my amendments.

Amendments (No. 418 to 421) were, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Hon. Members, we now take up Amendment Nos. 422 to 431 by Shri Rishang Keishing. Mr. Keishing, are you pressing?

SHRI RISHANG KEISHING (Manipur) : Madam, I withdraw my amendments. But I want to make only two points before the hon. Prime Minister. The loyal and law-abiding people in the insurgency-affected areas are suffering, and they are suffering at the hands of the insurgents, who call themselves as the freedom fighters. I request that the Government of India should lend effective help to the State Government in the restoration of law and order and in countering the criminal activities of the insurgents, and help the law-abiding people.

Amendments (No. 422 to 431) were, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN : We now take up Amendment Nos.432 to 453 by Shri Santosh Bagrodia. Mr. Bagrodia, are you pressing?

SHRI SANTOSH BAGRODIA : Madam, I withdraw my amendments. But I just want to say one thing. The hon. Prime Minister has just now stated that he will call a special meeting on the issue of drought in Rajasthan, where all the MPs should be present. I can assure him all of us will be present. Let him call the meeting before the 13th of March.

Amendments (No. 432 to 453) were, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN : We now take up Amendment Nos.454 to 476 by Shri Tarini Kanta Roy. Mr. Roy, are you pressing?

SHRI TARINI KANTA ROY (West Bengal) : No, Madam. I withdraw my amendments. But I request the Government to take up seriously the matter that I have mentioned in Amendment No. 476, that is, the control of wide-spread land erosion in West Bengal.

Amendments (No.454 to 476) were, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN : We now take up Amendment Nos. 477 to 493 by Shri Pranab Mukherjee. Are you pressing, Mr. Mukherjee?

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Madam, except Amendment No.481, I seek the indulgence of the House to withdraw my Amendments. I would just read my Amendment No.481. It says, "but regret that the Address fails to mention about the gross misuse of POTA in number of cases including detaining a person who is a minor (12 years old) despite the solemn assurances given to both Houses of Parliament by the Union Home Minister that POTA will not be misused".

Madam, in reply to a question in this very House, the Union Home Minister had responded by saying that so far as his assurances were concerned, those were limited only to the action taken by the Union Government. If POTA was misused by the State Governments, the Union Home Ministry did not have any responsibility. Madam, when, the POTA was issued - I am not going into the long history - in the form of an Ordinance, this House had rejected the Ordinance; it was approved by both

Houses of Parliament and the assurances were solemn. That Act was passed by Parliament. It is the inherent responsibility of the Government of India to implement an Act passed by the Parliament. Moreover, in respect of POTA, there is specifically section 16 which provides that both the Union Government and the State Governments can appoint review committees to ensure whether there has been any misuse of it or not. If the Government gives an assurance that all the constitutional and legal safeguards provided in the Act will be implemented, the Union Government will monitor that there is no misuse of POTA - as I gave one example in the text of the Amendment itself - another example was, an 80-year old person was detained under POTA - I would withdraw my amendment. I would request the hon. Prime Minister to give an assurance and assuage the feelings of this Ho:.:e that they will take all care to ensure that POTA is not misused. Subject to that, we will take that decision. May I request the hon. Prime Minister to respond to this suggestion of mine?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu) : Madam, I will take just two minutes. I am standing up here because this is a very important issue. The POTA was actually enacted on the hope that it will cover the anti-social elements and terrorists. At that time, when we sought an assurance from the Government, the Government had given a categorical assurance that it won't be misused or abused. But, in practice, it is now being misused throughout the country. ...*(Interruptions)*... The very pitiful thing is that the Parliament has enacted the law, and the very same Parliament's Member has become a victim of POTA. ...*(Interruptions)*...

SHRI P.G. NARAYANAN : Madam, he cannot raise this issue here. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : Mr. V. Gopalsamy and Mr. Nedumaran were arrested. ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN (Tamilnadu) : He is supporting the killers of Rajiv Gandhi. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : Let them give their opinion. ...*(Interruptions)*... Madam, what I am saying is this. When an assurance was given by the Government of India, the Government of Tamil Nadu has misused POTA.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Order, order. ...*(Interruptions)*... You have made your point. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : The Government of Tamil Nadu has misused POTA. ...*(Interruptions)*... Madam, keeping in mind... ...*(Interruptions)*...

SHRI P.G. NARAYANAN : Madam, it is not correct. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Virumbi, please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : Madam, in view of all these things, we still expect an assurance from the Government that this is a very serious matter; otherwise, many more people will be arrested under POTA. However, the Address of the President is above politics. That also, we keep in mind. ...*(Interruptions)*... POTA is being misused.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please, please. ...*(Interruptions)*... Just one second. ...*(Interruptions)*...

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU : Madam, as far as Tamil Nadu is concerned. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : This is not politics. ...*(Interruptions)*... This is not a fight between the DMK and the AIADMK. This is a fight between democracy and anti-democracy. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please take your seat. ...*(Interruptions)*... May I ask you to please sit down? ...*(Interruptions)*... In the morning, I was very happy that there was unanimity on one issue between the DMK, the AIADMK and the Congress. ...*(Interruptions)*... Please sit down. The Leader of the House wants to say something.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : This is not a fight between the DMK and the AIADMK. This is a fight between democracy and anti-democracy.

SHRI KAPIL SIBAL : Madam,...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Let him respond to something. Then, I will give you a chance. ...*(Interruptions)*... I would allow you. Let him finish. We want to hear him first.

THE MINISTER OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH) : Madam, do you want me to respond now or to respond later?

THE DEPUTY CHAIRMAN : He also wants to add something. He has Amendment No. 494.

SHRI KAPIL SIBAL : Madam, I have given Amendment No. 494 which reads as follows, "But regret that there is no mention in the Address about recent reports regarding the misuse of POTA; requiring that appropriate amendments in POTA be immediately effected to prevent its gross misuse". I just want to mention, Madam, that the other day, when the question came up, the hon. Home Minister was here. I put it to the hon. Home Minister that just as in TADA the Central Review Committees were set up, and State Committees were set up, the same should be done in the context of POTA, now that we have section 60. The hon. Home Minister had said that in a federal structure the Central Government had no role to play in the execution of laws as far as the State Governments were concerned. I pointed out that we have the Central Review Committees, and, unfortunately, while the law is in place for all this while, no Committees have been set up. This shows their seriousness!

You know, the other day, in Jharkhand, several people were arrested under POTA, and, suddenly, the Government announced, "We will withdraw all the cases under POTA." This kind of arrests and withdrawal, both, in public interest, is not right. A wrong message is being sent to the people of this country that political parties and Governments are misusing POTA for their partisan interest. This should not happen. We need an explanation from the hon. Prime Minister.

SHRI JASWANT SINGH : Madam, the hon. Pranab Mukherjee and some other hon. Members-and now hon. Kapil Sibal have spoken about POTA, and I do wish to, on behalf of the Government, assure all hon. Members that the Government will take all steps within its Constitutional and legal rights to ensure that provisions of POTA are not misused. ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL : Will you set up Review Committees? *...(Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN : I now put Amendment Nos. 477 to 493 to vote.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I would like to suggest, Madam, that you put all the Amendment Nos. 477 to 493, except Amendment No.481, to vote. Let us deal with it separately, because I wanted an assurance; one part of the assurance has already come; and, as for the other part, I am telling the Government that it is within the Act itself; under section 60 a Review Committee can be set up and it can be set up by the Union Government and it can be set up by the State Government. What is the difficulty of the Government to give that assurance?

SHRI JASWANT SINGH : Madam Deputy Chairman, so far as provisions in the Act, what is contained or inherent, are concerned, certainly, the aspect of the committee establishment is under the consideration of the Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now, I can put Amendments for withdrawal.

Amendment Nos. 477 to 493, were by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now Amendment No. 494 by Shri Kapil Sibal.

SHRI KAPIL SIBAL : Madam, in view of the assurance given by the Leader of the House, I withdraw the Amendment.

Amendment No.494 was, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN : All the Amendments are withdrawn now. I shall now put the motion to vote.

The question is:

> "That an Address be presented to the President in the following terms:-

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 17, 2003."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The House now is adjourned for an hour, for lunch.

The House then adjourned, for lunch, at thirty-nine minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at forty minutes past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) in the Chair.

THE BUDGET (RAILWAYS), 2003-04 -- CONTD.

लाला लाजपत राय (पंजाब) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा रेल बजट पेश किया है। यह बजट इस बात का सबूत है कि अवाम के अंदर रद्देअमल इतना अच्छा है कि बच्चा-बच्चा यह कह रहा है कि ऐसा बजट आज तक पेश नहीं किया गया है। बजट अच्छा ही नहीं है बल्कि यह एक ग्रोथ ओरिएन्टिड बजट भी है। इसकी वजाहत मैं आगे चलकर करुंगा। लेकिन ऐसा कोई तबका नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं जिसको इसका लाभ नहीं पहुंचेगा। नई रेलवे पटरियां बिछाना, नई रेलगाड़ियां चलाना, किराए भाड़े कम करना, बड़ी आयु के गरीब लोगों को सहूलियतें देना, ये सब बातें इसकी परिचायक हैं कि रेलवे बजट बहुत अच्छा है। मैंने बजट के अंदर जो ग्रोथ का जिक्र किया है, इससे मैं यह साबित करना चाहता हूं कि रेल मंत्री जी ने पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की किराए की दरों को कम करने के लिए कहा है। रेलवे फ्रेट कम करने से हमारी इकोनोमी की ग्रोथ बढ़ेगी और सभी परिवारों को इसका फायदा पहुंचेगा। सात से दस परसेंट तक रेलवे भाड़ों में कमी करने का ऐलान किया गया है। रेल मंत्री जी ने यह भी कहा है कि तेल कम्पनियों के साथ मशविरा करने के बाद मैं इन भाड़ों को और भी कम करने का हिसाब बनाऊंगा। मंत्री जी से इस बारे में मेरा यह कहना है कि अगर उन कम्पनियों के साथ बात करने से भाड़ा कम करने से लाभ पहुंचेगा कंज्यूमर को पास ऑन होगा, फिर तो ठीक है, उनसे बात करनी चाहिए। नहीं तो रेल मंत्री जी को अपने प्लान की वजाहत कर देनी चाहिए। पैट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ को-आर्डिनेशन करके, इस बात को फोलो-अप करना चाहिए कि रेल भाड़ा कम करके कंज्यूमर को इसका लाभ पहुंचता है। ऐसा ही दूसरा कदम है, शताब्दी और